दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 57* ❑ *अंक-18* ❑ *दिल्ली* ❑ *जुलाई 2019 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

मोदी जी का मिशन ''एक नेशन-एक इलेक्शन''

डा. सुमनाक्षर

'एक राष्ट्र–एक चुनाव' के प्रस्ताव को 19 जून, 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें 40 में से 24 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने किनारा किया। इन विपक्षी पार्टियों में बसपा अध्यक्ष मायावती, तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रुमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालीन और तेलुगुदेशम् पार्टी के प्रमुख चन्द्रबाबू नायडू ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह भी इस विषय से सहमत नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि बैठक में पेश किया गया प्रस्ताव सरकार का ऐजन्डा नहीं है, बल्कि देश का ऐजन्डा है। सब दलों को विश्वास में लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। यदि विचारों में कोई मतभेद होगा तो उसका भी सम्मान किया जायेगा।

इस बैठक में तय हुआ कि 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' के प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी पक्षों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक समिति गठित करेंगे जो निश्चित समय–सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी।

देश में संविधान के 1950 में लागू होने के पश्चात् तदनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव 1952, 1957 तथा 1967 में कराए गए। 1962 के तीसरे आम चुनाव के दौरान केरल से लोकसभा का चुनाव ही कराया जा सका जबकि अन्य सभी विधानसभाओं और लोकसभा, दोनों के चुनाव एक साथ कराए गए। इस उपलब्धि पर हैरत में पड़े सर एंथनी ईडन, यूनाइटेड किंग्डम के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था ''मेरा मानना है कि अभी तक सुशासन के नजरिये से जो तमाम प्रयोग किए गए हैं, उनमें संसदीय प्रणाली में प्रवेश के लिए भारत का उपक्रम सर्वाधिक रोचक है। एक विशाल उपमहाद्वीप अपने करोड़ों लोगों को स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है, जिसे हमारे जैसे एक छोटे देश में आने में सदियों की एक धीमी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। यह बड़ा साहसिक कार्य है। भारत प्रक्रिया हमारी नकल भर नहीं है, बल्कि यह इस कदर बड़े गुणित स्वरूप वाली है, जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसका एशिया पर इस कदर प्रभाव पड़ना लाजिमी है, जिसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल, नतीजा कुछ भी निकले हमें उनका सम्मान करना चाहिए जो इस प्रयास को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं।''

संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग और राजनीतिक गुणा–भाग का ही नतीजा है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव कराने से बचा जाने लगा। 1952 में सम्पन्न पहले आम चुनाव में कांग्रेस केन्द्र के साथ ही राज्यों में भी सत्तारूढ़ हुई थी। केरल के लोगों ने 1957 में समूचे देश को उस समय चौंका दिया था जब उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राज्य में विजयश्री दिला दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इंदिरा गांधी, जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, उन्होंने कहा था कि राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की विश्व में सर्वप्रथम चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाने के लिए 'मुक्ति संघर्ष' आरम्भ किया जाए। नतीजन, केरल में 1960 में नई विधानसभा के लिए चुनाव कराने पड़े। इसी के साथ तीसरे आम चुनाव के दौरान केरल अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव से अलग पड़ गया। अलबत्ता, निर्वाचन आयोग ने 1967 में हुए चौथे आम चुनाव के दौरान फिर से यथास्थिति को पुनर्स्थापित कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1972 में आम चुनाव समय से पूर्व कराकर चुनाव प्रणाली में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के सिलसिले को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद से यह सिलसिला फिर नहीं जम सका। इस प्रकार पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने का सिलसिला पूर्णतः भंग हो गया।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सम्पादकीय

मोदी है तो मुमकिन है

चुनाव आयोग ने 16वीं लोक सभा के चुनावों की तिथियों का एलान करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के यह चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 दिन मतदान होगा और 16 मई को मतगणना के साथ उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे जिससे कि बहुमतवाली विजेता पार्टी अपनी नई सरकार बना सके। इसके बाद पूरे देश में चुनाव हलचल शुरू हो गई। अब तक 2004 से 2014 तक पिछले दस सालों में प्राधनमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसकी लोकप्रियता भ्रष्टाचार, घोटाला, दलाली, महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, दमन, शोषण, भाई भतीजावादी, लूट–खसोट आदि के कारण खत्म हो चुकी थी, देश की जनता का मन कांग्रेस पार्टी से ऊब चुका था, इसलिए वह चाहती थी कि नई सरकार उस पार्टी की हो जो देश के भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, घोटाला, कालाधन, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, दबंगों की लूट–खसोट व आतंक से छुटकारा दिला सके।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 16वी लोक सभा का 2014 का यह चुनाव गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोटी की अगवाई में लड़ा। वह गुजरात में तीसरी बार चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने गुजरात का विकास कर देश के सामने 'गुजरात विकास मॉडल' रखा था और अपने चुनावी रैलियों व भाषणों में देशवासियों को विश्वास दिलाया कि वो कांग्रेसी शासन के भ्रष्टाचार, घोटालों, महंगाई, बेरोजगारी, वंशवाद, भाई–भतीजावाद से छुटकारा दिलाकर देश को सुसम्पन्न सर्वप्रिय, भय–भूख–अत्याचार मुक्त सरकार देंगे जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाली के साथ रह सकेगा।

भाजपा ने 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनावों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का नुमायन्दा पहले ही घोषित कर दिया था, जिसके 'गुजरात विकास मॉडल' ने लोगों को पहले से ही प्रभावित कर रखा था। और अब नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी धुंआधार भाषणों ने उन पर जादुई असर किया। वह जहां–जहां चुनावी रैलियां करते वहां–वहां लोगों का सैलाब 'मोदी–मोदी' के नारे लगता उमड़ पड़ता था, पर समाज में दलित, शोषित, अल्पसंख्यकों का एक वर्ग ऐसा भी था जो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी से भयभीत और डरे हुए थे।

देश के दलित, शोषित और अल्पसंख्यकों को यह कहकर डराया जाता है कि भाजपा ब्रह्मणवादी पार्टी है जो उन्हें कुचलकर रख देगी और गुजरात का मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन्दुवादी नेता है जिसे अल्पसंख्यक फूटी आंख एक क्षण भी नहीं सुहाते। अगर भाजपा को वोट दिया और चुनाव में उसके जीतने पर नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने पर भारत में दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों का जीना दुभर हो जायेगा।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के सभा–सम्मेलनों में देश में जहां भी हम जाते, वहीं दलित–शोषित व अल्पसंख्यक लोगों से उपरोक्त वाले सुनने को मिलती। हमारे बार–बार उन्हें समझाने, उनके अन्दर व्याप्त डर का निराकरण करने और उन्हें निर्भीकता के साथ जीने का आश्वासन देने के बावजूद हमें बार बार कहना पड़ता कि 'न तो मोदी भेड़िया है, और न ही काला नाग है भाजपा' इससे सम्बन्धित विशेष लेख हमने हिमायती

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

सम्पादकीय का शेष...मोदी है तो मुमकिन है

के अंक (फरवरी 2014) में अंक लिखा और अलग से दस हजार इस लेख की प्रतियां चुनाव के दौरान दलित, शोषित, अल्पसंख्यक लोगों के बीच वितरित कीं। इसका उन पर प्रभाव पड़ा और उनकी समझ आई कि उनको जानबूझ कर भाजपा और उसके प्रस्तावित भावी प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उन्हें भड़काकर गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद दलित–शोषितों व अल्पसंख्यकों ने अपनी सामूहिक बैठक करके निर्णय लिया कि वे अबकी बार अपने वोटों को बंटने नहीं देंगे, और इस बार उनका थोक में सभी वोट 'भाजपा' को जायेगा ताकि नरेन्द्र मोदी को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाया जा सके ओर फिर उनकी सरकार हमारे उत्थान, कल्याण, विकास के लिए कार्य करेगी, ताकि उन्होंने चुनाव में जो नारा दिया है–'सबका साथ, सबका विकास' साकार हो सके।

16वीं लोकसभा के चुनावों में दलित, शोषित व अल्पसंख्यकों ने उत्साह के साथ भाग लिया और एकजुट हो कर नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को निर्भीकता के साथ वोट दिया। 16 मई, 2014 को मत गणना के बाद जब लोकसभा के नतीजे आये तो 543 के लोकसभा सीटों में से उसकी सीढ़ियों को चुमा।

नरेन्द्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का नया राष्ट्रपति चुनने की घोषणा हो गई। इस राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर किये बैठाया जाये, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श करने लगीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सुझााव पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ गोविन्द को अपना उम्मीदवार घोषित किया जो उस समय बिहार के राज्यपाल थे और उससे पूर्व संसद (राज्यसभा) तथा भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके थे। भाजपा द्वारा एक दलित को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाये जाने पर देश के समूचे दलित समाज में खुशी की लहर फैल गई। कांग्रेस पार्टी को भी रामनाथ गोविंद के नाम का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि उसके पास राष्ट्रपति चुने जाने के लिए वांछित मत उपलब्ध नहीं थे, पर उसने प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप श्रीमती मीरा कुंमार को अपना प्रत्याशी बनाकर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर दिया। जहां पर वह बुरी तरह पराजित हुई। भाजपा का दलित राष्ट्रपति का सपना पूरा हुआ। आशा से भी अधिक मत पाकर श्री रामनाथ गोविंद भारत के राष्ट्रपति बन गये।

व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर वे बड़े व्यापारी इस 'जी.एस.टी. के दायरे में आ गये, जो चोरी करके टैक्स बचाते थे और देश के खजाने में टैक्स का पैसा न देकर अपनी तिजोरियां भरते थे। जी.एस.टी. के एकरूपता से कर का ढांचा ठीक हो गया, टैक्स चोरी बंद हो गई और देश को टैक्स मिलने से देश के विकास व प्रगति की योजनायें सरपट दौड़ने लगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने गरीब, बेसहारा, उपेक्षित, बेरोजगार, किसान व मजदूरों के लिए जो योजनायें बनाई उन्हें जन–जन तक पहुंचाने के लिए कारगर उपाय भी किये, जिसके परिणाम 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें मिली आशा से भी अधिक सफलता के रूप में मिला। 2014 से पहले ही सरकारें जिन मद्दों को छोटा समझकर उनकी ओर ध्यान नहीं देती थी, नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उन योजनाओं को प्राथमिकता देकर सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया, ऐसी योजनाओं में से प्रमुख हैं–

1. स्वच्छ भारत अभियान 2. खुले में शौचालय से मुक्ति–शौचालय अभियान योजना 3. गैस चूल्हा–उज्ज्वला योजना 4. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना 5. कौशल विकास

और उन आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में भारतीय सेनिकों पर गोला–बारूद से औचक हमला, जिसमें 42 भारतीय सेनिक शहीद हो गये थे, की घटना के जवाब में नरेन्द्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक (हवाई हमले) करके वहां पनप रहे आतंकवादियों के अड्डों को समूल नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने के नरेन्द्र मोदी सरकार के सैन्य अभियान के राष्ट्रवाद के सामने पूरा देश नतमस्तक हो गया और अपने गिला–शिकवा भूल कर सबके मुंह पर एक ही बात थी–''मोदी है तो मुमकीन है।''

भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अन्दर घुसकर बालाकोट के आतंकी अड्डों को तो नष्ट किया ही, पर जब बदले की भावना से पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर हवाई हमला किया तो हमारे हवाई जबांज विंग कमांडर अभिनन्दन ने उसके हवाई जहाज को मार गिराया, पर खुद के हवाई जहाज में आग लगने के कारण उसे विवशतावश पाकिस्तानी सीमा के अन्दर उतरना पड़ा–वहां पाकिस्तानी सेना ने उसे बन्धक बना लिया। पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्व–दबाव डाले जाने के कारण पाकिस्तान से विंग कमाडंर 'नये भारत' के सपने को साकार करेंगे।

देश के दलित–शोषित, उपेक्षित, वंचित लोगों को अब साम्प्रदायिकता के अपने सिद्धान्त को बदलना होगा। हमें अब जातिवादी राजनीति से भी ऊपर उठना होगा। बाबा साहब बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने तो बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी–'व्हाट गांधी एंड हिज कांग्रेस हेज डन विद शडयूल्डकास्टस्' (गांधी और उसकी कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए क्या किया है) इसमें उन्होंने दलितों के साथ गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जो उपेक्षा की थी, उसे दर्शाया गया है और इनसे सावधान रहने के लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने चेताया है। पर हम बाबा साहब डा. अम्बेडकर को अपना भगवान और मुक्तिदाता मानते हैं, पर जब राजनीति की बात है तो जातिगत राजनीति और कांग्रेस पार्टी की वंशवादी नीति का मोह नहीं त्यागते।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हम दलित, शोषित, उपेक्षित व वंचित के समीप ज्यादा पाते हैं। वह कहते ही नहीं, साकार करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले बाबा साहब डा. अम्बेडकर

भाजपा ने सर्वाधिक 282 सीटों पर जीत हासिल की और उसके एन.डी.ए. गठबन्धन को 336 लोकसभा सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 44 सीटों तक सिमट कर रह गई। दलित–शोषित अल्संख्यकों की अकेली पार्टी का दम भरने वाली बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुला।

देश का दलित–शोषित–अल्पसंख्यक लोगों में अत्यन्त खुशी थी कि अबकी बार उनका वोट बेकार नहीं गया और उन्होंने अपने वोट एक साधारण से व्यक्ति–'चायवाले नरेन्द्र मोदी' को देकर उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया।

'चाय वाला'–नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव में बहुमत पाकर 26 मई, 2014 को शपथ लेकर देश के 15वें प्रधानमंत्री बन गये और उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल गठन करके नई सरकार बना लिया। साधारण लोग खुश थे कि अब उनका अपना नरेन्द मोदी देश का प्रधान मंत्री बन गया है और अब उनके अच्छे दिन आने वाले है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब डा. अम्बेडकर का स्मरण करते हुए नतमस्क होकर उनका धन्यवाद किया जिनके बनाये गये भारतीय संविधान की बदौलत वे देश के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। संसद भवन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कानपुर के एक छोटे से गांव में दलित परिवार में जन्मा रामनाथ राष्ट्रपति भवन में 'महामहिम रामनाथ कोविंद के रूप में देश का 'राष्ट्रपति' बन गया। यह करामात श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी भाजपा की है, जिन्होंने जिगर खोलकर देश के दलित, अछूत, उपेक्षितों के प्रतिनिधि को प्राथमिकता देकर देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दूसरा बड़ा काम 'नोटबन्दी' का था। उन्होंने देश में चालू पांच सौ और हजार रुपयों के नोटों के चलन पर रोक लगा दी और उसके स्थान पर पांच सौ और दो हजार रुपये के नोटों की नई मुद्रा चालू की। यह नोटबन्दी 'गरीबों' के पक्ष में थी और जिन्होंने काले धन के रूप में असंख्य नोट जमा करके रखे थे, उनके लिए दुःखदायी थी। इससे कुछ हद तक काले धन पर रोक लगी और उसका फायदा गरीबों को हुआ। नरेन्द्र मोदी जी का यह कदम भी ऐतिहासिक था।

इसके अलावा देश में केन्द्र व राज्यों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर सेवा कर अलग अलग था। इससे एकरूपता लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में 'जी.एस.टी.' (गुडस् सर्विस टैक्स) लागू किया जिससे लोगों पर दोहरे टैक्स की मार न पड़े और एकरूपता बनी रहे। इससे छोटे योजना 6. मुद्रा लोन योजना 7. जनधन खाता योजना 8. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना 9. किसान कल्याण राशि योजना 10. हर घर बिजली–गैस योजना।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐसी दर्जनों योजनाओं ने उन्हें जन नेता ही नहीं, घर–घर में लोकप्रिय बना दिया। साधारण से साधारण व्यक्ति तक उन योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचा और वे उनसे प्रभावित हुए, इसलिए उनके लिए चुनाव में न कोई पार्टी थी, न सरकार, न अन्य कोई राजनेता। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी के मुंह से एक ही आवाज निकलती थी–''मोदी–मोदी–मोदी–अबकी बार फिर मोदी।''

विरोधी पार्टियों के गलत प्रचार के कारण जो कुछ युवा, दलित–शोषित लोग भारतीय जनता पार्टी

पार्टी (भाजपा) के खिलाफ थे कि अभी तक बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, कालाधन विदेश से नहीं लाया जा सका है, देश में उत्पीड़न और गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, पर उनके सामने मोदी सरकार की राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की घटनाओं की याद दिलाई जाती तो मोदी जी के गुणगान गाने लगते। जब पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद, अभिनन्दन की सकुशल वापसी हुई। इससे और सैन्य पराक्रम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ख्याति, कद, काठी और नाम सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंच गया, और 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में घर कर गई उनकी लोक–प्रियता इस 2019 के चुनाव में सुनामी में बदल गई, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटें मिली थीं, वहीं मोदी जी के राष्ट्रवाद के नारे के कारण भाजपा को 303 सीटें मिलीं। और उसके एन.डी.ए. गठबन्धन को 353 सीटें मिलीं। उसका मत प्रतिशत भी बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया, मोदी के प्रति रिकॉर्ड एकतरफा वोट मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी के सामने जाति–धर्म की सारी दीवारे ध्वस्त हो गई। उनके प्रति इस देश के युवाओं का न सिर्फ बेहतहा प्यार है। बल्कि दीवानगी भी आसीम है। तभी उनकी जुबान पर एक ही नारा है–''मोदी है तो मुमकिन है।'', ''मोदी भरोसे का नाम है।''

स्वयं मोदी जी 2014 के चुनावों में 'सबका साथ–सबका विकास' के जिस नारे के कारण चुनाव जीते थे, अब 2019 की लोकसभा चुनाव प्रचण्ड बहुमत से जीत कर 'सबका साथ–सबका विकास' से आगे बढ़कर सबका विश्वाास' जितने के लिए आगे बढ़ रहे है। हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी प्रधानमंत्री की अपनी दूसरी पारी में का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था–''बाबा साहब डा. अम्बेडकर जी के बनाये भारतीय संविधान के कारण ही वह प्रधानमंत्री बने हैं।'' अब 2019 के लोकसभा चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, उसके बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल खत्म होने पर नया राष्ट्रपति पद पर नये–नये कयास लगाये जा रहे थे, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने निर्णयों से लोगों को हमेशा चौंकाते रहते हैं। ऐसा ही निर्णय उन्होंने रामनाथ कोविंद का नाम नये राष्ट्रपति के लिए लिया, उससे सब राजनीतिज्ञों के अनुमान धराशायी हो गये क्योंकि दलित समाज के रामनाथ कोविंद के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दलित समाज को दलित समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी का आभार जताना चाहिए, क्योंकि डा. के.आर. नारायणन के बाद रामनाथ कोविंद को दूसरा दलित राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके लिए समूचा दलित समुदाय उनका आभारी है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बाबा साहब के जीवन की मुख्य घटनाएं

• एम.सी. विमल

13 अक्टूबर, 1935 को बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं यह मेरे बस में नहीं था, परन्तु हिन्दू धर्म में रह कर मरूंगा नहीं'' इस घोषणा को पूरा करने के लिये 14 अक्टूबर, 1956 को हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धम्म ग्रहण किया था। उन्होंने नागपुर में बौद्ध दीक्षा समारोह सफल पूर्वक सम्पन्न कराने के बाद 17 अक्टूबर, 1956 को वह रेल द्वारा दिल्ली वापस आये। दिल्ली आने पर अपने कई अधूरे कार्य पूरे करने की उनको चिन्ता सता रही थी। दूसरी ओर दिन प्रतिदिन अपने गिरते हुये स्वास्थ्य के प्रति वह बहुत चिन्तित थे। बौद्धमय भारत बनाने की कई योजनायें उनके मस्तिष्क में घूम रही थी। ''अगर मुझे मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य ने साथ दिया और मैं जीवित राह, तो दो वर्षों के अन्दर सारे भारत को बौद्धमय बना दूंगा।'' बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ प्रकाशित कराने की उन्हें जल्दी थी। मुम्बई जैसे दीक्षा कार्यक्रम देश के मुख्य–मुख्य शहरों में आयोजित कराने की योजनायें उनकी प्राथमिकताओं में थीं।

उन्हीं दिनों 14 नवम्बर से 19 नवम्बर, 1956 तक काठमांडू, नेपाल में विश्व बौद्ध मातृत्व सम्मेलन हो रहा था। स्वास्थ्य ठीक न होते हुये भी वह नेपाल गये। सम्मेलन में ''बौद्ध धम्म और कम्यूनिज्म'' पर भाषणा दियां देख कर 30 नवम्बर, 1956 को वायुयान द्वारा कुशीनगर से दिल्ली वापस आये।

4 दिसम्बर, 1956 को अन्तिम बार वह संसद गये

तीर्थयात्राा से बाबा साहब बहुत थक गये थे। कुछ समय आराम किया 11 दिसम्बर, 1956 को सायं दिल्ली में मथुरा रोड़ पर बौद्ध कला की मूर्तियों की प्रदर्शनी देखने गये। दूसरे दिन दो दिसम्बर को तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा के सम्मान में अशोक बुद्ध विहार महरौली (नई दिल्ली) में आयोजित समारोह में भाग लेने शाम को गये। स्वास्थ्य ठीक न होने से वह मंच से ऊपर नहीं जा सके और वहीं नीचे आराम कुर्सी पर बैठ गये। उस दिन परम पावन दलाई लामा और अन्य बौद्ध विद्वानों तथा भिक्खुओं को महाथेरा, धम्मवर ने जो अशोक बुद्ध विहार के इंचार्ज थे बाबा साहब को आमंत्रित किया। तथागत बुद्ध के 25वें शताब्दी महापरिनिर्वाण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये दलाई लामा बौद्धगया चले गये। किन्तु बाबा साहब वहीं आराम कुर्सी पर बैठ रहे। वहाँ उपस्थित लोग अपने मुक्तिदाता बाबा साहेब अम्बेडर के पैर छू कर आत्मियता प्रकट कर रहे थे। और बाबा साहब के पांव पर अधिक दबाव पड़ा तो बाबा साहब का ध्यान अखबार से हटा और उन्होंने पर लेटे–लेटे देश के लाखों करोड़ों शोषितों, पीड़ितों पद दलितों की विकराल समस्याओं पर चिन्तन मनन करते रहते थे। जब सारा संसार सो जाता तब उन्हें दलितों पर हो रहे क्रूरतम अत्याचारों और जुल्मों की याद सताती थी, चिन्ता के कारण बाबा साहेब को नींद नहीं आती थी और वह भावुक हो जाते थे।

भारत का संविधान लिखते समय विश्राम के अभाव में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हो गये थे। सोने से पहले रात में मधुमेह बीमारी का इन्सोलीन इन्जेक्शन लगवाना पड़ता था। उनकी डाक्टर पत्नी सविता अम्बेडकर ने प्रतिदिन की भांति रात में लगभग बारह बजे इन्सोलीन इन्जेक्शन सोते पर लगाया। मेडिकल साइग्स के अनुसार यदि इन्सोलीन की मात्रा अधिक हो जाये तो उसके दुष्प्रभाव से मृत्यु हो सकती है। अतएव बाबा साहब डा. अम्बेडकर को इन्सोलीन हानिकार सिद्ध हुई।

राजधानी दिल्ली से मुम्बई पार्थिव शरीर दिल्ली से मुम्बई लाया गया

बाबा साहब डा. अम्बेडकर की कोठी 26 अलीपुर रोड़ पर भारी जन समूह एकत्रित था। अब तक रात के आठ बज गये। पार्थिव शरीर दिल्ली से जी.बी. रोड में कोठों पर खड़े लोगों ने ऊपर से फूल मालायें अर्पित कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। रात के ग्यारह बजे संसद भवन तक जन सैलाब पैदल चलकर शव वाहन के साथ आया। पालम हवाई अड्डे पर एक विशेष विमान दिल्ली से मुम्बई पार्थिव शरीर ले जाने के लिये तैयार खड़ा प्रतीक्षा कर रहा थ्षा। जिसका उड़ान भरने का दस बजे रात का समय निर्धारित था, विलम्ब हो जाने से शवयान सीधे पालम ले जाया गया। हवाई अड्डे पर भारी संख्या में श्रद्धालु जनता पहुंच चुकी थी। दिसम्बर माह की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और अब तक रात के बारह बज गये थे।

विमान में शव के साथ सविता अम्बेडकर, भदंत आनन्द कौसल्यायन, सोहन लाल शास्त्री, इंजि. श्री भोसले, शंकरानन्द शास्त्री, नानक चन्द रत्तू, सेवक सुदामा, एम.आर. भारद्वाज, पूरन चन्द, तुलादास, पंडारकर सहित ग्यारह लोग बैठ गये। चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई लोग रो पड़े और फूल मालायें अर्पित किया। देखते ही देखते डकोटा विमान आकाश में विलीन हो गया।

मुम्बई महानगर की उत्तर दिशा में शान्ताक्रुंज विशाल हवाई अड्डा के बाहर हजारों लोग जमा थे। बाबा थी। शव को कोठी के एक कमरे में फूल मालाओं से सजाकर रखवाया गया। साथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई। मोमबत्ती, धूपवत्ती जलाई गई। बुद्ध वंदना की गई। दोपहर तक लोग दर्शन करते रहे और श्रद्धा भक्ति से फूल मालायें अर्पित करते रहे। महाराष्ट्र के लोगों को निधन का समाचार मिलते ही यहां आपने लगे। नागपुर, नासिक, मनमाड़, सोलापुर और औरंगाबाद से मुम्बई के लिये जनता को लाने के लिये स्पेशल रेल चलाई गई थी। लोग रेलों में भर–भर कर मुम्बई पहुंच रहे थे। दहाड़ें मार कर रो रहे थे। पार्थिव शरीर के निकट यशवन्त राव अम्बेडकर, सविताबाई और बौद्ध भिक्खु बैठे थे। दूसरी ओर पत्रकार, फोटोग्राफर, संसद सदस्य ओर अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता और अधिकारी बैठे थे।

दिन चढ़ता गया, अन्तिम दर्शन करने वालों की भीड़ भी बढ़ती गई। राजगृह तक पहुचने का प्रयास कर रहे लोगों की भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई थी कि पुलिस बल को भी बीच–बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा था। शुक्रवार 7 दिसम्बर, 1956 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर दो बजे राजगृह, दादर से सागर तट, शिवाजी पार्क

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा ''यदि हम हिंसात्मक क्रान्ति के बिना साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिये एक मात्र उपाय बौद्ध धम्म की स्थापना ही है। सम्मेलन में संसार भर के बौद्धों की ओर से उस सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीलंका के बौद्ध विद्वान प्रोफेसर डा. मललसेकर ने बाबा साहेब का स्वागत किया।

डा. अम्बेडकर की बौद्ध स्थलों की यात्रा

काठमांडू, नेपाल में विश्व बौद्ध मातृत्व सम्मेलन सम्पन्न होने के बाद बाबा साहब काठमांडू से 20 नवम्बर 1956 को तथागत बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बनी गये और वहाँ के बौद्ध अवशेषों को देखा। लुम्बनी में बौद्ध अवशेषों की दुर्दशा देख कर बाबा साहब भावुक हो गये, उनकी आँखों में आंसू टपक पड़े। कुछ समय वहाँ चिन्तन मनन किया और वह लुम्बनी से बनारस आये। यहां सारनाथ में बौद्ध धवंसावशेषों का अवलोकन किया। तोड़े गये अशोक स्तम्भ के खण्डों को भी देखा। धम्मेक स्तूप वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पंचवर्षीय सेमिनारों को प्रथम धम्म उपदेश दिया था। बनारस विद्यापीठ में विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुये बाबा साहब ने सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा ''जो कार्य शंकराचार्य ने हिन्दुओं के लिये किया वही कार्य अब वे बुद्ध धम्म के लिये करेंगे।'' बौद्धगया बौद्व स्थलों को भी अपनी छड़ी से श्रद्धालु को धमकाया कि झुकना छोड़ो। यह क्रम घंटों चलता रहा। जिसे देखकर वहाँ उपस्थित भिक्खु आश्चर्य चकित रह गये। उस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 4 दिसम्बर, 1956 को कुछ समय के लिये बाबा साहेब राज्यसभा गये, जिसके वह सदस्य थे। वहाँ उपस्थित संसद सदस्यों से बातचीत की। शाम को निजी सचिव से कुछ महत्वपूर्ण पत्र लिखवाये और कुछ संदर्भ टाइप करवाया।

रहस्यमय घटना

5 दिसम्बर, 1956 को सवेरे देर तक सोते रहे। जागने पर दैनिक कार्यों से निवृत हो कर सदैव की भाँति अतिथियों से मिलते रहे और बातचीत करते रहे। उस दिन रात साढ़े नौ बजे जैन मुनि का बाबा साहब से मिलने का समय निर्धारित था। जैन मुनि आये और दूसरे दिन 6 दिसम्बर, 1956 को दिल्ली मे जैन धर्म की एक सभा में पधारने के लिये बाबा साहब से प्रार्थना की, बाबा साहेब ने कहा यदि स्वास्थ्य ठीक रहा तो अवश्य आऊंगा। रात को साढ़े दस बजे आश्वासन पाकर जैन मुनि चले गये। थोड़ी देर बाद भोजन किया। ''बुद्ध और उनका धम्म'' ग्रंथ की भूमि की टाइप प्रतिलिपि तथा कुछ अन्य पत्रों को रत्तू से मेज पर रखने को कह कर लाठी के सहारे धीरे–धीरे कमरे में सोने चले गये।

प्रायः रात के ग्यारह–बारह बजे से पहले वह कभी सोते नहीं थे। बिस्तर मुम्बई ले जाने के लिये एक ट्रक पर फूल मालाओं से मंच बनाया गया। मंच पर पार्थिव शरीर रखवाकर भारी जन समूह के साथ पालम हवाई अड्डे की ओर जुलूस के साथ शव यात्रा शुरु हुई। लोग त्रिरण का उच्चारण करते धीरे–धीरे शव यात्रा के साथ पैदल चल रहे थे। अपने मसीहा के अन्तिम दर्शन करने राजधानी की जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। कोठी से पालम तक भारी जन समूह फैला हुआ था। हजारों स्त्रियॉ शोक मे डूबी हुई सड़कों पर खड़ी थीं। दबे–कुचले, दीन–दुःखी परिवारों की अधिकतर स्त्रियां फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी देखा जा सकती थीं। कड़ाके की ठंड से वह कांप रहीं थीं। शवयान निकट पहुंचने पर वे भाव विहल श्रद्धा सुमन अर्पित करती थीं।

राजधानी दिल्ली की जनता ने महात्मा गांधी की शवयात्रा को जाते देखा था। 6 दिसम्बर, 1956 को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डा. अम्बेडकर की शवयात्रा को भी देखा। परन्तु आज से बढ़कर श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धांजली और करूणा जनक दृश्य राजधानी के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया होगा। जो शोषितों, पीड़ितों तथा दलितों के मसीहा की शवयात्रा में देखा।

दिल्ली के बड़े–बड़े बाजारों से शवयात्रा गुजरती हुई आगे बढ़ती रही। गली, बाजरों में खड़ी प्रतीक्षा कर रही जनता दुःखी और व्याकुल थी। साहब का पार्थिव शरीर दिल्ली से एक विशेष विमान लेकर आ रहा था। प्रतीक्षा करते रात के दो बज गये। महाराष्ट्र की जनता अपने प्रिय नेता को देखने को व्याकुल थी। शोक में डुबी हुई जनता को प्रतीक्षा करते दस बारह घंटा से अधिक समय हो चुका था। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। लाखों भक्त और अनुयायी मुम्बई की सड़कों पर होश–हवास गंवाये घूम रहे थे। महाराष्ट्र की जनता अब और प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं थी। वह बड़ी ही दुःखद व खतरनाक घड़ी थी। उस दिन कुछ भी हो सकता था। प्रातः 7 दिसम्बर, 1956 शुक्रवार को शान्ताक्रुंज मुम्बई हवाई अड्डे पर विमान पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा छा गया, लोग दर्शन को आतुस थे। जोर–जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ रहीं थीं। यह करुणा का दृश्य था। हवाई अड्डे पर दादर 'राजगृह' दस कि.मी. दूर है, एक खुले ट्रक पर शव को रखा गया जो धीरे–धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे कुछ मोटर कार और जन समुद्र रोता बिलखता चला। दस कि. मी. लम्बी सड़के के दोनों ओर शोक में डूबी जनता बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। माहिम और कुर्ला से रानी बाग तक क्षेत्र के लोग भीड़ के कारण रात में सो न सके। मार्ग के चारों ओर जनता उमड़ पड़ी।

7 दिसम्बर, 1956 को सवेरे शवयान राजगृह पहुंचा। अब तक यहाँ दो लाख से अधिक जनता एकत्र हो चुकी चौपाटी के शमसान घाट के लिये शवयात्रा शुरु हुई।

शवयात्रा : राजगृह से शिवाजी पार्क मुम्बई के शमसान घाट तक

दोपहर के ढाई बजे शुक्रवार 7 दिसम्बर, 1956 को राजगृह से अन्त्येष्टि के लिये शवयात्रा आरम्भ हुई। एक मोटर ट्रक पर बने मंच पर बाबा साहब का पार्थिव शरीर फूल मालाओं से सजा हुआ था, जो धीरे–धीरे आगे बढ़ रहा था। पीछे–पीछे तीन चार ट्रक श्रद्धांजलि में अर्पित फूल मालाओं से लदी हुई चल रही थी। भिक्खु संघ त्रिशरण का उच्चारण करते हुए अपार जनता की अटूट कतारों के साथ पैदल चल रहे थे। बाबा साहब के अन्तिम दर्शन के लिये अब तक चारों ओर से लोग भागते दौड़ते आ रहे थे। रेलों में भर–भर कर देश के कोने–कोने से लोग आ रहे थे।

मुम्बई महानगर का कारोबार बन्द हो गया था। कहीं कोई मजदूर नहीं मिल रहे थे। वे अपने परिवारों के साथ अपने प्रिय बाबा साहब को श्रद्धांजली देने के लिये पहुंच गये थे। नगर में नित्य सफाई का कार्य बन्द हो गया और मिलों का काम ठप्प पड़ा था। जहाजों में सामान उताने के लिये मजदूर नहीं मिल रहे थे। शवयात्रा के साथ व्यवस्था के लिये पुलिस दल भी चल रहा था। स्त्रियों का इतना भारी जमावाड़ा इससे पूर्व शायद ही कहीं देखा गया हो, जो बाबा साहब की अन्त्येष्टि के अवसर पर देखा गया।•

हिमायती
4 / जुलाई (प्रथम), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 जुलाई, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 28 जून, 2019

पृष्ठ 1 का शेष...मोदी जी का मिशन–''एक नेशन-एक इलेक्शन''

5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1975 में एक वर्ष बढ़ाया जाना, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा विधानसभाओं को 1978 में भंग किया जाना, इंदिरा गांधी द्वारा जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में 1980–81 में उत्तर दिया जाना, एक साथ चुनावों की संभावना को समाप्त करते रहे। यह भी गौरतलब है कि 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा कांग्रेस की राज्य सरकारों की बर्खास्तगी और 1980–81 में इंदिरा गांधी द्वारा जनता पार्टी की राज्य सरकारों के साथ वैसा ही व्यवहार दोनों चुनावों में समन्वय ला सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। बाद के वर्षों में दोनों स्तर के चुनावों के बीच असमन्वय और राज्य चुनावों में बिखराव बढ़ता ही गया।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं कराए जाने से देश को खासी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, आम चुनाव कराने में लगभग 45,000 करोड़ खर्च होते हैं। इसके अलावा, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार कितना खर्च करते हैं, आकलन नहीं लगाया जा सकता। हालांकि निर्वाचन संबंधी कानून में उम्मीदवारों के खर्च की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन इस कानून की अनदेखी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के एक आकलन के अनुसार, हाल में पांच राज्यों में चुनाव के समय करीब 60,000 करोड़ रुपए बाजार में आ गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उम्मीदवार किस कदर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं।

चुनाव आयोग ने इस विचार का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया था कि इस पर खर्च अधिक आयेगा और कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बहरहाल, स्थायी समिति की रिपोर्ट और चुनाव आयोग के पक्ष का विश्लेषण करने के बाद कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे को दो हिस्सों में बांट दिया है। चुनाव आयोग ने मई में कानून मंत्रालय को दिए अपने जवाब में कहा कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करता है लेकिन इस पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। चुनाव आयोग ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वी.वी.पी.ए.टी.) मशीनें खरीदनी होंगी। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से कराने के लिए ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी. मशीनें खरीदने के लिए लगभग 9,284.15 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। संसदीय समिति ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा 'मशीनों को हर 15 वर्ष में बदलने की जरूरत होगी जिस पर फिर बड़ा खर्च आयेगा। इसके अलावा इन मशीनों के रखरखाव पर भी भारी भरकम राशि खर्च होगी।' निर्वाचन संबंधी कानून के अनुसार, सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं और सदन का कार्यकाल आपातकाल की अधिसूचना को छोड़कर अन्य मामलों में नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप लाने के लिए राज्य विधानसभाओं के सदनों में अवधि या तो बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद तीन और चार में संशोधन की जरूरत होगी। ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार को यह देखना होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संयुक्त चुनाव कराने के लिए ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए।

अगर देश में संयुक्त रूप से चुनाव हुए तो इससे होने वाले लाभ पर हमें एक बार गौर करना होगा। पूरे देश में केवल एक ही मतदाता सूची होगी। अभी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों की अलग–अलग मतदाता सूचियां हैं। अक्सर मतदाता का नाम एक सूची में होता है, लेकिन दूसरी सूची में नहीं होता, जिससे वह मतदान से वंचित हो जाता है। देश को प्रतिवर्ष चुनाव से राहत मिलेगी और सरकारों व जनता को पांच वर्ष तक अपने–अपने कार्यों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। रोज–रोज के चुनावों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कहीं मॉडल–'कोड ऑफ कंडक्ट' के कारण विकास रुकता है तो कहीं नौकरशाह चुनावों की दुहाई देकर विकास कार्यों से बचते हैं। देश में चुनावों में हिंसा रोकना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसमें पुलिस, अर्ध–सैनिक बल और कभी–कभी सेना भी बुलानी पड़ती है। यदि पांच वर्ष के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाएगा, बल्कि सम्भवतः वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनने की दिशा में एक मजबूत कदम भी बढ़ाएगा। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ होने लगें तो सरकारी खजाने के धन की भी बचत होगी और राजनीतिक दलों के धन की भी। राजनीति की शह से होने वाले भ्रष्टाचार में भी कमी आ सकती है। एक लाभ यह भी होगा कि राजनीतिक दलों को रह–रहकर चुनाव की मुद्रा में आने की जरूरत नहीं रहेगी और वे सारा ध्यान अपने एजेंडे पर केंद्रित कर सकेंगे।

विपक्षी दलों के हौंसलों को चित्त करने की यह सत्तापक्ष भाजपा की एक नई कवायद है। 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' को सिरे चढ़ाते मुमकिन है कि 2022 में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हो जायें। इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने वाले किसी दल के लिए ऐसा फैसला लेना आसान नहीं होगा। अभी 2022 तक 17 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी शामिल हैं। मोदी–अमित शाह की रणनीति भाजपा शासित कई राज्यों

सम्पादकीय का शेष....मोदी है तो मुमकिन है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाबा साहब डा. अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ हैं जिनके भारतीय संविधान के कारण एक पिछड़ी जाति के गरीब परिवार का व्यक्ति होते हुए वह विशाल भारत का प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए उनके इस ऋण से उऋण होने के लिए उन्होंने बाबा साहब डा. अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी स्मृतियों को भव्य रूप देने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने डा. अम्बेडकर के जीवन, व्यक्तित्व व कृतित्व से जुड़े पांच स्थलों का विकास करके 'डा. अम्बेडकर पंचतीर्थ स्थल' का नाम दिया। इन पांच तीर्थस्थलों में पहला तीर्थ स्थल है–जन्मभूमि, महू (इन्दौर) म.प्र.। दूसरा तीर्थ स्थल है–दीक्षा भूमि, नागपुर (महाराष्ट्र), तीसरा तीर्थ स्थल है–चैत्य भूमि, दादर (महाराष्ट्र), चौथा तीर्थ स्थल है–डा. अम्बेडकर मेमोरियल, लन्दन (ब्रिटेन), पांचवां तीर्थ स्थल है–डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 26, अलीपुर रोड, दिल्ली। इसके अलावा नई दिल्ली, जनपथ पर डा. अम्बेडकर सभागार केन्द्र स्थापित किया गया, जहां विशाल पुस्तकालय के साथ सभा सम्मेलन करने के लिए सभागार (ओडोटोरियम) हैं जहां बाबा साहब डा. अम्बेडकर के आन्दोलन से जुड़ी संस्थायें अपनी सभा, संगोष्ठी, सम्मेलन कर सकती है।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर के मिशन से जुड़े देश के अम्बेडकरवादियों, बुद्ध धर्म अनुयायियों और दलित–शोषित–वंचित लोगों को बाबा साहब डा. अम्बेडकर के इन पंचतीर्थ स्मारकों की स्थापना और निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने निश्चित अवधि में इन भव्य ऐतिहासिक स्मृतियों का निर्माण कराकर देश–विदेश के बाबा साहब डा. अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए लोकार्पित किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति अपराध निरोधक एक्ट–1989 को जमानती बना देने से इस 'एस.सी./एस.टी. एस्ट्रोसिटी एक्ट' की शक्ति को कमजोर कर दिये जाने पर मोदी सरकार ने नया अध्यादेश लाकर इस एक्ट को पुनः यथावत शक्तिवान बना दिया। इसके लिए भी दलित समाज उनका आभारी है और इसका धन्यवाद उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से जिताकर किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती में 300 पाईंट रोस्टर की जगह 13 पाईंट रोस्टर लागू कर दिया था जिससे दलित लोगों की शिक्षण संस्थानों में भर्ती एक तरह प्रतिबंधित हो गई थी, इसके लिए मोदी सरकार ने पुनः अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करके 13 पाईंट रोस्टर की जगह पुनः 300 पाईंट रोस्टर लागू कर दिया। इससे दलित समाज के शिक्षितों के लिए नौकरी के द्वार पुनः खुल गये। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन शिक्षित दलित समाज के लोगों ने खुलकर एकजुट होकर मोदी जी को वोट किया और धन्यवाद स्वरूप उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया।

दलित, शोषित, उपेक्षित, वंचित लोगों को अपना उज्ज्वल भविष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में सुरक्षित दिख रहा है। इसलिए वे तन–मन–धन से उनके साथ हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बाद चुनाव हों तो उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। रोज–रोज के चुनावों में सबसे अधिक क्षति विद्यालयों–विश्वविद्यालयों के छात्रों को होती है, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आता है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक तो अक्सर मतदाता सूची बनाने से लेकर चुनाव में मतगणना तक सभी कार्यों के लिए बाध्य किए जाते हैं, जो देश के भावी–कर्णधारों के साथ एक खिलवाड़ है। इसके अलावा देश की विविधता के चलते चुनावों में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और जातीय–उन्माद बढ़ने की भी सम्भावना बहुत बढ़ जाती है, जो सरकारों के लिए सिरदर्द और समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। यदि वास्तव में संसद, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और जनता इस सुझाव पर संजीदगी से विचार करें तो पूरे देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संयुक्त रूप से जरूर कराए जा सकते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व का मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है।

अब तो अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पिको ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामरिक कदम उठाने की प्रशंसा करते हुए कहा–''मोदी है तो मुमकिन है।''

– डा. सुमनाक्षर

की सरकारें भंग कर इसके साथ ही चुनाव कराने का इरादा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा 2022 में लोकसभा के साथ–साथ 20–25 राज्यों के चुनाव हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना भी परवान चढ़ सकती है। अगर परिस्थितियां ठीक रहीं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व कर्नाटक राज्यों के चुनाव भी इसी के साथ करवाये जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिशन–'एक नेशन–एक इलेक्शन' (एक देश–एक चुनाव) का यह कदम जहां देश को आगे ले जाने वाला 'नई इंडिया' का एक सपना है, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 'शायनिंग इंडिया' की तरह जोखिम भरा भी है जहां 2004 में सत्ता भाजपा के हाथ से खिसककर कांग्रेस के पाले में चली गई थी, पर अब 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' का सपना साकार करना, मोदी है तो मुमकिन है। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009